भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1838
उत्तर देने की तारीख 29 जुलाई, 2026

सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम का कार्यान्वयन

1838. श्री गोविन्द मकथप्पा कारजोल:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रव्यापी आपदा चेतावनी और आपातकालीन संचार के लिए शुरू किए गए स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम (सीबीएस) का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रणाली के विकास, परीक्षण और राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन पर हुए कुल व्यय का ब्यौरा क्या है और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (सी-डॉट) और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रदान किए गए वित्तपोषण का ब्यौरा क्या है;

(ग) कर्नाटक सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ इस प्रणाली के एकीकरण की वर्तमान स्थिति और इसके कार्यान्वयन का ब्यौरा क्या है;

(घ) इसकी शुरुआत के बाद से अलर्ट की संख्या, कवर किए गए राज्यों और अनुमानित मोबाइल उपयोगकर्ताओं की संख्या को दर्शाते हुए इस प्रणाली के माध्यम से जारी किए गए आपदा अलर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस प्रणाली की विश्वसनीयता, बहुभाषी क्षमता, दिव्यांगजनों के लिए पहुंच, डेटा गोपनीयता, साइबर सुरक्षा और आवधिक परीक्षण सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क), (ख) और (ग) सी-डॉट द्वारा विकसित स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम (सीबीएस) को दिनांक 2 मई, 2026 को माननीय संचार मंत्री द्वारा राष्ट्रव्यापी स्तर पर लॉन्च किया गया है। इसे 99.82 करोड़ रुपये के परिव्यय सहित सी-डॉट और एनडीएमए के बीच समझौता ज्ञापन

के तहत सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (कर्नाटक सहित) में सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं में मोबाइल फोन पर आपदा चेतावनी और आपातकालीन अलर्ट के लिए लागू किया गया है।

(घ) एसडीएमए द्वारा दिनांक 19 जुलाई, 2026 तक विभिन्न आपदाओं के लिए कुल 132 सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट अनेक राज्यों में जारी किए गए हैं। इनका विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	सीबी अलर्ट की संख्या
1	उत्तर प्रदेश	79
2	मध्य प्रदेश	10
3	राजस्थान	9
4	छत्तीसगढ़	10
5	बिहार	7
6	ओडिशा	5
7	महाराष्ट्र	3
8	हरियाणा	3
9	उत्तराखंड	2
10	असम	1
11	आंध्र प्रदेश	1
12	केरल	1
13	त्रिपुरा	1
सीबी अलर्ट की कुल संख्या		132

चूंकि सेल ब्रॉडकास्ट एक प्रसारण आधारित तकनीक है, इसलिए अलर्ट को लक्षित मोबाइल टावर से जुड़े सभी फोनों पर प्रसारित किया जाता है।

(ङ) दूरसंचार विभाग ने मोबाइल हैंडसेट निर्माताओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित सभी 22 भाषाओं में सेल ब्रॉडकास्ट का सपोर्ट करने के लिए अनिवार्य किया है, जिसमें दिव्यांगजनों के लिए अलर्ट की पहुंच सुनिश्चित करने सहित अलर्ट सामग्री को पढ़ने के साथ-साथ, विशिष्ट अलर्ट टोन और वाइब्रेशन पैटर्न को भी सपोर्ट करना होगा। सेल ब्रॉडकास्ट मैसेज डेटा गोपनीयता को प्रभावित नहीं करते हैं।

कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया (सीईआरटी-इंडिया) सूचीबद्ध एजेंसी द्वारा सुरक्षा कमियों को दूर करने के लिए समय-समय पर सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन एप्लीकेशनों का परीक्षण और स्कैन किया जाता है और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस) द्वारा सुरक्षा, संप्रभुता और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे में तैनाती के लिए इसकी उपयुक्तता की पुष्टि करते हुए इसे एक विश्वसनीय दूरसंचार उत्पाद के रूप में मान्यता दी गई है।

*****